

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	राष्ट्रीय पोषण माह-2025 : राजस्थान का दूसरा स्थान
2.	गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान का पहला ई-बस मेन्यूफैक्चरिंग प्लांट : घिलोठ 2. राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) : पचपदरा 3. नवीन औद्योगिक क्षेत्र : धुवाला (भीलवाड़ा) 4. 'नव विधान-न्याय की पहचान' प्रदर्शनी 5. NCISM रैंकिंग में राजस्थान 6. 'मिस टीन यूनिवर्स 2025' : जयपुर 7. एशियन यूथ गेम्स 2025 (बहरीन) में राजस्थान 8. राजस्थान का पहला वरिष्ठजन क्लब : अटल क्लब जयपुर 9. जैसलमेर में भैरव बटालियन का युद्धाभ्यास
4.	भारत-कनाडा संबंध
5.	संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
6.	समावेशी और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण
7.	REDD+ कार्यक्रम
8.	WMO-ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन
9.	प्रशियन ब्लू कैप्सूल
10.	असंतुलित उर्वरक सब्सिडी
11.	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और स्टेबलकॉइन
12.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC)

--:1:--



राजस्थान परिदृश्य



राष्ट्रीय पोषण माह-2025 : राजस्थान का दूसरा स्थान



चर्चा में क्यों?

- 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2025 तक संचालित 'राष्ट्रीय पोषण माह, 2025' में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया।



निदेशालय जनसंविकृत बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग



8वां राष्ट्रीय पोषण माह

17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
17 सितंबर 2025 को शुभारंभ

- आंगनवाड़ी केंद्रों पर - स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, बचपन की देखभाल-शिक्षा और स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों को बढ़ावा।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विशेष पंजीकरण मुहिम
- 75,000 हेल्थ कैंप - महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस

"वर्ष 2047 तक सुपोषित भारत के निर्माण हेतु भारत सरकार पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुपरफूड और जागरुकता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए, इस मुहिम का हिस्सा बनें।"

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025

UTKARSH
CLASSES

CIVIL
SERVICES



मुख्य बिन्दु:

- राष्ट्रीय पोषण माह, 2024 में राजस्थान ने चौथा स्थान प्राप्त किया था।
- राजस्थान में आयोजन : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा।
- संस्करण : अष्टम।

पोषण माह, 2025 की प्रमुख थीम्स :

- मोटापे की समस्या का समाधान।
- चीनी और तेल का सेवन कम करना।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE)
- शिशु और छोटे बच्चों के आहार के तरीके (IYCF)

राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष -3 राज्य :

स्थान	राज्य
प्रथम	गुजरात
द्वितीय	राजस्थान
तृतीय	छत्तीसगढ़

राज्य स्तर पर शीर्ष - 5 जिले:

स्थान	जिला
प्रथम	जोधपुर
द्वितीय	कोटा
तृतीय	बीकानेर
चतुर्थ	चूरू
पंचम	हनुमानगढ़

--3--

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



- ज्ञातव्य है कि राजस्थान राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा, 2025 (8 से 22 अप्रैल, 2025) और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' में भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पोषण अभियान:

- कुपोषण की समस्या के निराकरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा देश भर में 8 मार्च, 2018 को 'पोषण अभियान' की शुरुआत की गई।
- कुपोषण संबंधी समस्या के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए यह एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य** : समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण संबंधी कमियों में सुधार करना।

पोषण ट्रेकर ऐप:

- 'पोषण ट्रेकर' एक मोबाइल आधारित ऐप्लिकेशन है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NEGD) के माध्यम से शुरू किया गया।
- इस ऐप द्वारा बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, कम वजन की व्यापकता की सशक्त पहचान और पोषण सेवा वितरण की ट्रैकिंग की जा रही है।
- साथ ही इस ऐप के माध्यम से आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवाओं के कुशल वितरण में सहायता एवं मार्गदर्शन भी प्रदान किया जा रहा है।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु:

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS):

- **कार्यक्रम की शुरुआत** : 2 अक्टूबर, 1975

उद्देश्य :

- 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए आधार तैयार करना।
- मृत्यु दर, बीमारियों, कुपोषण और स्कूल ड्रॉपआउट की दर को घटाना।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में राजस्थान में 363 बाल विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

--:4::--

गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना

चर्चा में क्यों?

- राजस्थान राज्य बजट-2025-26 की अनुपालना में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सभी 41 जिलों के एक-एक ब्लॉक में 'गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना' की शुरुआत की गई।

मुख्य बिन्दु:

41 जिलों के चयनित ब्लॉक:

ब्लॉक	जिला	ब्लॉक	जिला
भिनाय	अजमेर	रामगढ़	अलवर
गढ़ी	बाँसवाड़ा	सिणधरी	बालोतरा
चौहटन	बाड़मेर	भूसावर	भरतपुर
करेड़ा	भीलवाड़ा	शाहबाद	बारां
बीकानेर	बीकानेर	सिकंदरा	दौसा
सैपळु	धौलपुर	गलियाकोट	डूंगरपुर
नावा	डीड़वाना-कुचामन	धमोतर	प्रतापगढ़
जालौर	जालौर	चाकसू	जयपुर
सम	जैसलमेर	झालरापाटन	झालावाड़
झुँझुनूँ	झुँझुनूँ	भादरा	हनुमानगढ़
मसूदा	ब्यावर	लाडपुरा	कोटा
बानसूर	कोटपूतली-बहरोड़	करौली	करौली
मेड़ता	नागौर	बाली	पाली

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



खंडार	सवाई माधोपुर	खंडेला	सीकर
पिंडवाड़ा	सिरोही	सादुलशहर	श्रीगंगानगर
उनियारा	टोंक	सराड़ा	सलूमबर
कोटड़ा	उदयपुर	कुंभलगढ़	राजसमंद
सेखाला	जोधपुर	आऊ	फलोदी
पहाड़ी	डीग	तिजारा	खैरथल-तिजारा
गंगरार	चित्तौड़गढ़	चूरू	चूरू
तालेड़ा	बूँदी		

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

- इस योजना के माध्यम से राजस्थान में कुल 41 ब्लॉकों में लक्षित विकास कार्यक्रम संचालित कर उन्हें विकसित ब्लॉक की श्रेणी में शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के जरिए सभी चिह्नित ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ, आधारभूत संरचना, कौशल विकास एवं सामाजिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार आधारित कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा।
- इसकी मॉनिटरिंग के लिए 39 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों को आधार बनाया गया है। योजना की विभिन्न स्तर पर निगरानी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति और जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय समितियाँ बनाई गई हैं।
- **बजट प्रावधान :** राजस्थान बजट 2025-26 में आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना के तहत कुल ₹75 करोड़।
- प्रत्येक ब्लॉक को ₹1.5 करोड़ (अनटाइड फंड) के रूप में दिया जाएगा।
- योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ब्लॉकों को वार्षिक पुरस्कार राशि दी जाएगी।

--6--

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



स्थान	पुरस्कार राशि
प्रथम स्थान	50 लाख रुपये
द्वितीय स्थान	35 लाख रुपये
तृतीय स्थान	25 लाख रुपये

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

- केंद्र सरकार द्वारा अविकसित जिलों के उत्थान के लिए जनवरी, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) 112 जिलों में शुरू किया गया।
- केंद्र सरकार एवं नीति आयोग द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के पाँच जिले - बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही शामिल हैं।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम से जिलों में आए सकारात्मक बदलाव, सफलता और विकास को ब्लॉक स्तर तक पहुँचाने के लिए जनवरी, 2023 में केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 27 ब्लॉक शामिल हैं।

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राजस्थान का पहला ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट : घिलोठ</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राज्य सरकार ने कोटपूतली-बहरोड़ के घिलोठ औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान के पहले ई-बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हेतु 65.56 एकड़ भूमि का आवंटन किया।राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत निजी क्षेत्र की कंपनी PMI इलेक्ट्रो मॉबिलिटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड को रीको के माध्यम से यह भूमि आवंटित की गई है।
2.	<p>राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) : पचपदरा</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, रीको ने RPZ एरिया में भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया की शुरुआत की।पचपदरा रिफाइनरी से 12 किमी दूर स्थित राजस्थान पेट्रो जोन अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस-वे और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 से जुड़ा हुआ है।राजस्थान पेट्रो जोन (RPZ) से प्लास्टिक व पॉलिमर प्रोसेसिंग, रबड़ व पीयू मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल टैक्सटाइल, रासायनिक एवं फार्मास्यूटिकल जैसे उद्योगों के जरिये राज्य में निवेश आकर्षित होगा।
3.	<p>नवीन औद्योगिक क्षेत्र : धुवाला (भीलवाड़ा)</p> <ul style="list-style-type: none">हाल ही में, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको) को भीलवाड़ा के धुवाला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने हेतु 82.60 हेक्टेयर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की।

4.

'नव विधान-न्याय की पहचान' प्रदर्शनी

- सीतापुरा (जयपुर) में आयोजित 'नव विधान -न्याय की पहचान' प्रदर्शनी के माध्यम से देश में लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों की समझ को आधुनिक पुलिस नवाचारों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।
- इस प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय गृह एव सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया।
- भागीदारी : 13 से 21 अक्टूबर, 2025 तक संचालित इस प्रदर्शनी में रिकॉर्ड 1.67 करोड़ से अधिक लोगों ने भौतिक और ऑनलाइन माध्यम से अवलोकन किया।

5.

NCISM रैंकिंग में राजस्थान

- राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (NIA), जयपुर ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसे ग्रेड-ए श्रेणी में शामिल किया गया है।
- ग्रेड-बी श्रेणी में राजस्थान के संस्थानों में महात्मा ज्योतिबा फुले आयुर्वेद कॉलेज, चौमूं (रैंक 88वीं) और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, उदयपुर (रैंक 93वीं) शामिल हुए।
- **जारीकर्ता** : नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (NCISM), नई दिल्ली।

6.

'मिस टीन यूनिवर्स, 2025' : जयपुर

- 'मिस टीन यूनिवर्स 2025' का ग्रैंड फिनाले जयपुर में आयोजित किया गया।
- इस आयोजन में भारत सहित 22 देशों की मॉडल्स ने भाग लिया। वेनेजुएला की अमीरा मोरेनो ने 'मिस टीन यूनिवर्स-2025' का खिताब जीता। वहीं, फिलीपींस की चियारा गॉट्सचॉक फर्स्ट रनरअप और संयुक्त राज्य अमेरिका की सबरीना फ्रुक्ट्स सैकंड रनरअप रहीं।

7.

एशियन यूथ गेम्स 2025 (बहरीन) में राजस्थान

- आयोजन तिथि : 22 से 31 अक्टूबर, 2025 तक।
- संस्करण : तीसरा।
- आयोजक संस्था : ओलम्पिक काउंसिल ऑफ एशिया।
- मुएथाई (Muay Thai) प्रतियोगिता : कुल 9 भारतीय खिलाड़ियों में से 4 राजस्थान से - विधि शर्मा, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता (जयपुर) और हर्षिता (जालौर)
- बालिका हैंडबॉल : सीकर निवासी ममता का चयन।
- रोड साइक्लिंग इवेंट : रोड साइक्लिंग को पहली बार यूथ गेम्स में शामिल किया गया है।
- कुल साइक्लिस्ट: 8 (4 महिला + 4 पुरुष) जिसमें राजस्थान से चयनित 5 साइक्लिस्ट : आलोक बिश्रोई, लोकेश चौधरी, आदित्य जाखड़, अंजलि जाखड़, रुक्मणि।

8.

राजस्थान का पहला वरिष्ठजन क्लब : अटल क्लब जयपुर

- हाल ही में, जयपुर ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने शहर के वरिष्ठजनों हेतु अटल क्लब/अटल उद्यान का लोकार्पण किया।
- यह राजस्थान का पहला ऐसा क्लब है, जो वरिष्ठों को समर्पित है।

9.

जैसलमेर में भैरव बटालियन का युद्धाभ्यास

- हाल ही में, जैसलमेर के लोन्गोवाला युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना की भैरव बटालियन और अश्रि पलटन द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया।
- भैरव बटालियन भारतीय सेना की हाल ही में निर्मित नई एलीट इकाई हैं, जिन्हें तेज और सटीक सैन्य अभियानों के लिए बनाया गया है।
- ये बटालियन साधारण पैदल सेना और स्पेशल फोर्स के बीच की कड़ी होंगी। इन बटालियनों में इंफैंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर डिफेंस जैसे अलग-अलग रेजिमेंट के सैनिक शामिल होंगे।
- नोट : जैसलमेर आर्मी स्टेशन में हाल ही में सम्पन्न आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन सेंटर, सैनिक यात्री मित्र एप और इक्विपमेंट हेल्पलाइन लॉन्च किए।



अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य



भारत-कनाडा संबंध



चर्चा में क्यों?

- भारत और कनाडा के विदेश मंत्रियों के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नया रोडमैप तैयार करने पर सहमति जताई।



मुख्य बिन्दु:

नए रोडमैप के मुख्य बिंदु

- कनाडा-भारत मंत्री-स्तरीय ऊर्जा संवाद को फिर से शुरू करने पर सहमति हुई।
- LNG और LPG के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा तथा तेल गैस खोज एवं उत्पादन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समिति को फिर से प्रारंभ किया जाएगा।
- ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी संधारणीय और कम-कार्बन उत्सर्जन वाली ईंधन तकनीकों पर सहयोग करने पर सहमति बनी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और फिनटेक जैसी नई तकनीकों में अनुसंधान हेतु साझेदारी पर विशेष जोर दिया गया।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्

चर्चा में क्यों?

- भारत सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् का सदस्य चुना गया। भारत निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। भारत को वर्ष 2026 से 2028 के तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है।

मुख्य बिन्दु:

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद्

- **परिचय:** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत एक अंतर-सरकारी संस्था है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है।
- **स्थापना:** इसे वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा।
- **सदस्य:** इसमें कुल 47 सदस्य देश हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रतिवर्ष चुनती है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल तीन वर्षों का होता है। कोई देश अधिकतम दो लगातार कार्यकाल के लिए ही सदस्य बन सकता है।

समावेशी और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण

चर्चा में क्यों?

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक व्यवस्था स्थापित हुई थी, उसे पैक्स अमेरिकाना कहा जाता है। यह व्यवस्था अब महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रही है।

मुख्य बिन्दु:

- ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका ने उदार लोकतंत्र, खुले बाजार और बहुपक्षीय सहयोग का समर्थन किया है। लेकिन हालिया घटनाक्रम अमेरिका के इस मॉडल से दूर जाने का संकेत देते हैं। इससे वैश्विक मामलों में नेतृत्व संबंधी शून्यता उत्पन्न हो रहा है।

पैक्स अमेरिकाना व्यवस्था के पतन के लिए जिम्मेदार कारक

- **विरोधाभासी कार्यवाहियां:** वियतनाम युद्ध, मध्य पूर्व में अमेरिकी हस्तक्षेप और वर्ष 2008 के वित्तीय संकट ने अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर किया है।
- **नीतिगत बदलाव:** अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की "अमेरिका फर्स्ट" नीति के तहत शामिल आक्रामक व्यापार नीतियों ने अमेरिकी प्रभाव पर प्रतिकूल असर डाला है।
- **बहुपक्षीय संस्थाओं का कमजोर होना:** अमेरिका द्वारा अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर हटने से उसकी सॉफ्ट पावर की छवि कमजोर हुई है।

चीन का बढ़ता प्रभाव

- अमेरिका की वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका के कमजोर पड़ने का फायदा उठाकर चीन स्वयं को बहुपक्षवाद के रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है तथा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी पहलों के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है।
- चीन अब 100 से अधिक देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है, जिससे इसका क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव मजबूत हुआ है।

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



- हालांकि, दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक विदेश नीति, मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे, ऋण जाल कूटनीति आदि चीन की सॉफ्ट पावर संबंधी छवि तथा इसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सीमित करते हैं।
- पैक्स अमेरिकाना के पतन से वैश्विक व्यवस्था अधिक खंडित (पैक्स मल्टीपोलारिस) हो सकती है। इससे भारत जैसे राष्ट्रों को जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे अधिक समावेशी और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण होगा।

भारत के लिए अवसर

- भारत रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से लीडरशिप वैक्यूम को भरना है।
- भारत, अपनी आर्थिक साझेदारियों में विविधता लाकर, निवेश को आकर्षित करके और वैश्विक व्यवस्था में आवश्यक सुधारों का समर्थन करके, प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को संतुलित कर सकता है।

--:14:--

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

REDD+ कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

- REDD+ कार्यक्रम के तहत संचालित उष्णकटिबंधीय वनों की कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं ने वनों की कटाई को कम करने में बड़ी सफलता हासिल की है।

मुख्य बिन्दु:

REDD+

- यह पहल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पक्षकार देशों द्वारा विकसित की गई है।
- REDD का अर्थ है, विकासशील देशों में 'निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कटौती'।
- प्लस (+) का अर्थ है जलवायु की रक्षा करने वाली वन संबंधी अतिरिक्त गतिविधियाँ जैसे कि, वनों का सतत् प्रबंधन, उनका संरक्षण, और वन कार्बन भंडारों का संवर्धन।
- इसके तहत, यदि कोई विकासशील देश वनों की कटाई कम करने में सफल होता है, तो उसे उत्सर्जन में कमी आधारित भुगतान प्राप्त हो सकता है। यह कार्यक्रम पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का भी हिस्सा है।

WMO-ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन

चर्चा में क्यों?

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने ग्रीनहाउस गैसों की स्थिति पर अपनी 21वीं ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन जारी की है।

मुख्य बिन्दु:

- **CO₂ रिकॉर्ड स्तर पर:** वर्ष 2024 में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) का स्तर 423.9 5 ppm तक पहुँच गया। यह 2023 की तुलना में 3.5 5 ppm अधिक है।
- यह 1957 में गणना शुरू होने के बाद से सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि है।
- **सबसे गर्म वर्ष:** वर्ष 2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, जहाँ वैश्विक तापमान औद्योगिक क्रांति-पूर्व स्तर से 1.55°C अधिक दर्ज किया गया। वैश्विक तापमान ने पेरिस समझौते की 1.5°C सीमा को पार किया।
- **क्लाइमेट फोर्सिंग:** वायुमंडल में अधिक समय तक रहने वाली ग्रीनहाउस गैसों में 54% की वृद्धि दर्ज की गई।
- मीथेन (CH₄) और नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O) का स्तर भी औद्योगिक क्रांति-पूर्व स्तरों से ऊपर बढ़ गया है।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

प्रशियन ब्लू कैप्सूल

📢 चर्चा में क्यों?

- भारत ने सीज़ियम-137 (Cs-137) संदूषण के दुष्प्रभाव को कम करने में उपयोगी प्रशियन ब्लू कैप्सूल्स इंडोनेशिया को भेजे हैं।

📌 मुख्य बिन्दु:

- Cs-137 रेडियोएक्टिव समस्थानिक है जो परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होता है। इसका उपयोग चिकित्सा उपकरणों और औद्योगिक गेजों में किया जाता है। इसके प्रभाव में आने पर जलन, रेडिएशन जनित बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।

प्रशियन ब्लू कैप्सूल

- प्रशियन ब्लू आँतों में रेडियोएक्टिव सीज़ियम और थैलियम को फँसाकर शरीर में उनके अवशोषण को रोकता है।
- यह इन हानिकारक तत्त्वों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे रेडिएशन का प्रभाव कम होता है। इस तरह यह स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान की संभावना को कम करता है।

आर्थिक परिदृश्य

असंतुलित उर्वरक सब्सिडी

चर्चा में क्यों?

- कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट रबी फसलों के लिए मूल्य नीति, विपणन सत्र 2024-25 में उर्वरकों से संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

मुख्य बिन्दु:

रिपोर्ट के प्रमुख मुद्दे

- **उर्वरक लाभ में कमी:** NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम) का प्रति किलोग्राम खाद्यान्न उत्पादन 12 किलोग्राम (1960-69) से घटकर 2020 में 3 किलोग्राम हो गया है।
- **सब्सिडी संरचना:** उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के कारण यूरिया का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। इससे पोषक तत्वों और साथ ही मिट्टी की उर्वरता में भी असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।
- **असमान उपयोग:** कुछ राज्यों और जिलों में उर्वरक का प्रति हेक्टेयर उपयोग आवश्यकता से अधिक है, जबकि अन्य में बहुत कम है।
- **आयात निर्भरता:** देश की 30% उर्वरक माँग आयात से पूरी होती है, जिसमें कच्चा माल और तैयार उर्वरक दोनों शामिल हैं।

CACP की सिफारिशें

- **यूरिया की कीमतों में चरणबद्ध वृद्धि:** यूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी का उपयोग फास्फोरस एवं पोटेशियम उर्वरकों के लिए किया जाना चाहिए।
- **एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन:** इसके तहत रासायनिक उर्वरकों, जैविक खाद और जैव-उर्वरकों को एकीकृत किया जाना चाहिए।

Daily Current Affairs

Date : 25 October, 2025



- **मृदा परीक्षण:** इसके तहत प्रयोगशालाओं को उन्नत करना, आधुनिक उपकरण स्थापित करना तथा रियल टाइम मृदा विश्लेषण और परामर्श सेवाओं के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना आदि शामिल करना।

उर्वरक संबंधी मुद्दों का समाधान

- पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी योजना
- धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधान मंत्री कार्यक्रम (PM-PRANAM/ पीएम-प्रणाम)
- **अन्य:** मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम-लेपित यूरिया, नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देना आदि।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:19:--

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) और स्टेबलकॉइन



चर्चा में क्यों?

- RBI गवर्नर ने अन्य केंद्रीय बैंकों को स्टेबलकॉइन की तुलना में CBDCs को बढ़ावा देने का सुझाव दिया।



मुख्य बिन्दु:

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और स्टेबलकॉइन:

- CBDC एक नई प्रकार की मुद्रा है, जो केवल डिजिटल रूप में होती है।
- केंद्रीय बैंक करेंसी को प्रिंट करने की बजाय एक ऐसी डिजिटल मुद्रा (डिजिटल सिक्के) जारी करता है जो आसानी से उपलब्ध होती है। इससे डिजिटल लेन-देन और पैसे भेजना सरल एवं तेज हो जाता है।
- स्टेबलकॉइन एक प्रकार की प्रोग्रामेबल क्रिप्टोकॉइन है, जिसका मूल्य किसी अन्य परिसंपत्ति प्रायः अमेरिकी डॉलर या अन्य मुद्रा से जुड़ा होता है।

स्टेबलकॉइन की तुलना में CBDC को प्राथमिकता देने की आवश्यकता क्यों है?

- **संप्रभु समर्थन:** CBDC को कानूनी मुद्रा माना जाता है। इसका अर्थ है कि सरकार इसे हर तरह के लेन-देन में स्वीकार और मान्यता देती है।
- CBDC एक विनियामक फ्रेमवर्क के तहत संचालित होती है, जिससे उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
- **सीमा-पार भुगतान:** CBDC अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी भुगतान को सरल और तेज कर सकती है। इससे स्विफ्ट (SWIFT) जैसे मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है।
- यह मौद्रिक नीति के साथ बेहतर तरीके से एकीकृत होती है। यह समावेशी और कम लागत वाली सार्वजनिक भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देती है।

भारत में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)

- भारत की CBDC को डिजिटल रुपया कहा जाता है।
- यह RBI द्वारा डिजिटल रूप में जारी की जाती है। इसमें भौतिक नकदी के समान ही सुविधाएँ होती हैं, जैसे उपयोग में सुविधा, RBI की गारंटी, फाइनेलिटी ऑफ सेटलमेंट आदि।
- यह उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहती है और इसका उपयोग किसी भी भौतिक नोट की तरह धन प्राप्त करने/ भेजने या लेन-देन के लिए भुगतान करने हेतु किया जा सकता है।
- **RBI वर्तमान में दो प्रकार की CBDCs संचालित कर रहा है:**
 - **रिटेल CBDC:** यह डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध है।
 - **होलसेल CBDC:** इसे बैंकों और अन्य लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थाओं के मध्य बैंकों के बीच भुगतान एवं प्रतिभूति लेन-देन के लिए उपयोग किया जाता है।

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC)</p> <ul style="list-style-type: none">■ भारत के विवेक मेनन को वर्ष 2025-2029 के लिए IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन (SSC) का नया अध्यक्ष चुना गया। <p>IUCN स्पीशीज़ सर्वाइवल कमीशन</p> <ul style="list-style-type: none">■ स्थापना: वर्ष 1949■ यह दुनिया के लगभग हर देश से जुड़े 10,500 से अधिक स्वैच्छिक विशेषज्ञों का विज्ञान-आधारित नेटवर्क है।■ यह IUCN को जैव विविधता संरक्षण, प्रजातियों के प्राकृतिक महत्व, और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य व कार्यप्रणाली में उनकी भूमिका से संबंधित जानकारी प्रदान करता है।

